

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 226 □ रायपुर, मंगलवार 8 सितंबर 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

समुद्र में अमेरिका का कहर इकाडोर का 5वां जहाज डुबोया

नई दिल्ली, 8 सितंबर (न्यूज चैनल)। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोमवार को प्रशांत महासागर में इकाडोर के एक जहाज को डुबो दिया। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज अपराधी संगठन लॉस चोनेरोस से जुड़ा था।



अमेरिकी कमान के मुताबिक, यह एक तैरता हुआ ईंधन केंद्र था। इसका इस्तेमाल समुद्र

में नशीली दवाओं की तस्करी के अभियानों को मदद देने के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में हुई। जहाज पर मौजूद लोगों को पहले उतार लिया गया। अब उन्हें इकाडोर के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। इसमें अमेरिकी सैन्यकर्मी एक जहाज पर चढ़ते दिख रहे हैं। इसके बाद ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आता है। आखिर में एक प्रक्षेपास्त्र जहाज से टकराता है और वह समुद्र में डूब जाता है। अमेरिकी कमान ने कहा कि उसकी सेनाएं पश्चिमी गोलार्ध में नशीली दवाओं की तस्करी को बढ़ावा देने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए सटीक और पेशेवर अभियान जारी रखे हुए हैं।

सत्य निकेतन इमारत हादसा: घायलों से मिलने एम्स पहुंची सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 8 सितंबर (न्यूज चैनल)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन की एक संकरी गली में लड़कों के छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रही 30 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत रविवार को भूभरा कर ढह गई। जमींदोज हुई इस इमारत हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने एम्स पहुंचीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैंने घायल बच्चों से मुलाकात की है। एक मजदूर यहां भर्ती है, जो अभी ठीक है। 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और एक बच्चा आईसीयू में है। मैंने परिजनों से भी मुलाकात की है।



चूहा- सुनती हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में तय नहीं होती जवाबदेही।
चुहिया- हां जी, तो राहुल भैया बता देवें कौन सी सरकार में तय होती है जवाबदेही।

तमिलनाडु: 1,020 करोड़ के घोटाले में धिरे पूर्व मंत्री केएन नेहरु पर एफआईआर, पार्टी फंड के नाम पर वसूली का आरोप

नई दिल्ली, 8 सितंबर (न्यूज चैनल)। डीवीएसी ने पूर्व मंत्री केएन नेहरु को मुख्य आरोपी और 12 अन्य लोगों को 1,020 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सरकारी टेंडर में बड़ी गड़बड़ी और रिश्तत लेने का आरोप है। एफआईआर में डीएमके नेता के भाइयों और डीएमके के दो पूर्व विधायकों एस. सुदर्शनम और जे.जे. एबेनेजर का नाम शामिल है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों की सिफारिश की, टेंडर की जानकारी साझा की। इसके साथ ही कथित तौर पर रिश्तत की रकम का हिसाब-किताब किया। सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय के दस्तावेज में दावा किया गया है कि डीएमके नेता ने वरिष्ठ नौकरशाहों तक पहुंचने में मदद की और टेंडर देने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि नगर प्रशासन और जलापूर्ति विभाग के पूर्व मंत्री ने अपने भाइयों को अपने करीबी सहयोगी के साथ मिलकर ठेकेदारों और



सरकारी कर्मचारियों से पार्टी फंड के नाम पर अवैध पैसे वसूलने की इजाजत दी थी। इसमें कहा गया है कि इस तरह 1,020 करोड़ रुपये का अवैध फायदा उठाया गया। यह अवैध वसूली कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत के 7.5 से 10 प्रतिशत के बराबर पार्टी फंड के तौर पर की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की 258 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर डीवीएसी की जांच के बाद शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया, जिसमें 2021 और 2025 के बीच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया है कि नेहरु मुख्य आरोपी थे। उनके भाई के.एन. मणिवन्न और एन. रविचंद्रन अवैध रिश्तत की वसूली और उसे वितरित करने में समन्वय कर रहे थे। इसमें आगे दावा किया गया कि नेहरु ने अपने भाइयों को अपने करीबी सहयोगी कवि प्रसाद के साथ समन्वय करने की अनुमति दी, ताकि ठेकेदारों और लोक सेवकों से अवैध रिश्तत एकत्र की जा सके, जो कथित तौर पर उन्हें दी जाती थी।

तेलंगाना विस में बीआरएस पर दोहरी कार्रवाई, दो एमएलसी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 8 सितंबर (न्यूज चैनल)। तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन सोमवार को सप्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव में बदल गया। बीआरएस के विधायक और एमएलसी काले रंग की टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। पार्टी का कहना था कि इन टी-शर्ट पर सरकार के 1,000 दिन के कामकाज और चुनावी वादों को लेकर सवाल लिखे थे। पुलिस ने उन्हें विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया। पुलिस का कहना था कि टी-शर्ट पर लिखे कुछ नारे आपत्तिजनक थे। इसके बाद बीआरएस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। केटीआर, टी. हरीश राव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया।

धमतरी जिले के 56 शासकीय विभागों का 47 करोड़ का बिजली बिल शेष

25 विभागों की कटी बिजली

स्मार्ट मीटर लगाने के बाद विद्युत विभाग की सख्ती, सीधे रायपुर मुख्यालय से हुई कार्रवाई



धमतरी, 8 सितम्बर (हाईवे चैनल)। जिले के शासकीय दफ्तरो का करोड़ों का बिजली सार्लों से बकाया है। जिसे जमा कराने विद्युत विभाग द्वारा पूर्व

में नोटिस भी जारी किया गया था। बाउजूद इसके बिजली बिल जमा नहीं कराया गया। जिस पर अब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद सख्ती बरती जा रही है। कल विद्युत विभाग द्वारा जिले के 25 शासकीय विभागों के विद्युत कनेक्शन काट दिये गये। जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित हुआ। और हड़कम्प मच गया। बता दे कि जिले के 56 शासकीय विभागों का लगभग 47.46 करोड़ बिजली बिल बकाया है। उक्त लाइन काटने की कार्रवाई आनलाईन सिस्टम रायपुर कंट्रोल रूम से हुई है। कल रोज की तरह शासकीय दफ्तरों में लोग अपने कार्यों को लेकर व



कर्मचारी अधिकारी पहुंचे, लेकिन बिजली बंद होने से वे गर्मी से परेशान हुए साथ ही काम भी प्रभावित हुआ। उपपंजीयक कार्यालय, जिला कोषालय, जनपद पंचायत, आबकारी कार्यालय, सहित अन्य विभागीय कार्यालयों व नगर निगम के कुछ उद्यान व शौचालयों के विद्युत कनेक्शन भी काटे गए। जिनसे आम जनता को भी असुविधा हुई।

“शासकीय विभागों का करोड़ों का बिजली बिल बकाया है जिन्हें जमा कराने पूर्व में नोटिस दिया गया था। कल सीधे रायपुर से आनलाईन सिस्टम से विभागीय कार्यालयों की विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई है।”

अनिल सोनी, ईई, विद्युत विभाग, धमतरी संभाग

इन पर है करोड़ों का बकाया

बिजली विभाग की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा बकाया ग्राम पंचायत नल-जल पर 29.87 करोड़ रुपए है। इसके बाद नगरीय निकाय नल-जल पर 5.05 करोड़, नगरीय निकाय सड़क बत्ती पर 3.78 करोड़, ग्राम पंचायत सड़क बत्ती पर 3.45 करोड़ और पुलिस विभाग पर 1.20 करोड़ रुपए का बकाया है। अन्य बड़े बकायादारों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 89.33 लाख, लोक निर्माण विभाग पर 44.98 लाख, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग पर 44.58 लाख, जल संसाधन विभाग पर 33.44 लाख तथा स्कूल शिक्षा विभाग पर 16.59 लाख रुपए का बकाया शामिल है। उपपंजीयक कार्यालय का बिजली बिल अप्रैल से अगस्त तक का नहीं पटा है। 98 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण उसका कनेक्शन काट दिया गया।

शोर रोकने निकले थे विक्रम, दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली, 8 सितंबर (न्यूज चैनल)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुरी संगीतकार सी. विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि विक्रम ने अपने फ्लैट के बाहर शोर मचाने और शराब पीने का विरोध किया था। इसके बाद वहां मौजूद डिलीवरी कर्मियों और ढाबा कर्मचारियों से एक नाबालिग को भी हिरासत में उनका विवाद हो गया। लिया गया है।



आरोपियों ने विक्रम को मुक्कों और घुंसों से बुरी तरह पीटा। मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उनका बेठा याइफाबा उन्हें तुरंत होली फैमिली अस्पताल ले गया। इलाज के दौरान विक्रम की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

राहुल बोले- शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस क्या कर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चोंगथम विक्रम सिंह मणिपुर के एक प्रसिद्ध संगीतकार, अपने घर के बाहर कुछ लोगों से शोर कम करने के लिए कहने नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए पीट-पीटकर मार डाला गया। एक पिता की अपने ही घर के बाहर, अपने ही देश की राजधानी में हत्या कर दी गई। ऐसी कई घटनाओं के बाद आज दिल्ली में रहने वाला हर पूर्वोत्तर परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या हम यहां सुरक्षित हैं? राहुल गांधी ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हैं? मामले की तेजी से जांच होनी चाहिए और दौषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। विक्रम जी के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने यह बात मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कही।

पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका 2019 का समन रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली, 8 सितंबर (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2019 में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एकल पीठ ने राहुल गांधी को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गिरगांव मजिस्ट्रेट की ओर से 28 अगस्त 2019 को जारी आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि उसे मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए आदेश में ऐसी कोई ‘कानूनी गलती या विकृति’ नहीं मिली, जिसके आधार पर अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा कि आदेश में कोई खामी नहीं है और इसलिए राहुल गांधी की याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने नवंबर 2021 के उस आदेश को जारी रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह के लिए टालने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान राहुल गांधी को मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला रहेगा।

नवा रायपुर में लगेगा गोल्फ का महाकुंभ 132 दिग्गज गोल्फर दिखाएंगे दमखम



कपिल देव करेंगे टूर्नामेंट का शुभारंभ, विजेंता को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम

रायपुर, 8 सितंबर (हाईवे चैनल)। नवा रायपुर एक बार फिर देश के बड़े पेशेवर गोल्फ आयोजनों में से एक की मेजबानी करने जा रहा है। डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई) की ओर से नवा रायपुर ओपन 2026 का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट में किया जाएगा। टूर्नामेंट में देश-विदेश के कुल 132 पेशेवर गोल्फर हिस्सा लेंगे और 21 करोड़ की पुरस्कार राशि के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। टूर्नामेंट की खास बात यह है कि महान भारतीय क्रिकेटर और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव 13 सितंबर को इसके शुभारंभ समारोह में मौजूद रहेंगे। टूर्नामेंट सप्ताह की शुरुआत इसी दिन प्रो-एम स्पर्धा से होगी। इसके बाद

14 सितंबर को आधिकारिक अभ्यास दौर खेला जाएगा और 15 सितंबर से मुख्य पेशेवर प्रतियोगिता शुरू होगी। नवा रायपुर ओपन 2026 में पेशेवर गोल्फर चार राउंड में खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। प्रतियोगिता में भारत के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ 18 विदेशी गोल्फर भी हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी से टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा का स्तर और बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय खिलाड़ियों में सप्तक तलवार, हनी बैसोया, वीर अहलावत, अक्षय शर्मा, ओम प्रकाश चौहान, खालिन जोशी, राशिद खान और मनु गंडास जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन खिलाड़ियों पर टूर्नामेंट के दौरान खास नजर रहेगी। नवा रायपुर के लिए यह साल पेशेवर गोल्फ के

लिहाज से खास है। 2026 में यहां डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई का यह दूसरा टूर्नामेंट होगा। लगातार बड़े पेशेवर आयोजनों की मेजबानी से नवा रायपुर का नाम देश के पेशेवर गोल्फ कैलेंडर में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। आयोजकों के मुताबिक, टूर्नामेंट केवल चार दिन की मुख्य प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा। 13 सितंबर को प्रो-एम मुकाबले के साथ गतिविधियां शुरू होंगी, जबकि 14 सितंबर को खिलाड़ी आधिकारिक अभ्यास दौर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 15 से 18 सितंबर तक मुख्य प्रतियोगिता खेली जाएगी। टूर्नामेंट के शुभारंभ समारोह में शामिल होने वाले कपिल देव ने नवा रायपुर को पेशेवर गोल्फ के लिए महत्वपूर्ण स्थल बनने की क्षमता वाला बताया है।

शिवपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय में बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान छात्राओं का स्कूल से कलेक्टर तक मार्च!

तनाव और थकान के चलते एक छात्रा अचानक बेहोश होकर गिरी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा

अंबिकापुर, 8 सितंबर (हाईवे चैनल)। सरगुजा जिले के शिवपुर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान 45 छात्राओं ने सोमवार को प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए बड़ा कदम उठाया। छात्राएं स्कूल से करीब 30 किलोमीटर दूर अंबिकापुर कलेक्टोरेट तक पैदल ही निकल पड़ीं। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद जब इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बस भेजकर छात्राओं को कलेक्टोरेट लाया गया। कलेक्टोरेट पहुंचने के बाद छात्राएं सीधे कलेक्टर अजीत वसंत से मुलाकात करने पर अड़ी रहीं। इसी दौरान तनाव और थकान के चलते एक छात्रा शिकायत की थी, लेकिन उनकी समस्याओं को समाधान नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते



गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में पिछले तीन महीने से बिजली की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा मेस में साफ-सफाई की स्थिति खराब है और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री की कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लग रही हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्राचार्य और स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की थी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते

छात्राओं ने पैदल अंबिकापुर जाने का फैसला किया। छात्राओं के मार्च की जानकारी मिलते ही आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ललित शुक्ला बेलकोट पहुंचे। उन्होंने छात्राओं को समझाने की कोशिश की और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ शिक्षकों ने भी छात्राओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं किसी अन्य अधिकारी से बातचीत के

लिए तैयार नहीं हुईं और कलेक्टर से ही मिलने की मांग करती रहीं। जहां शिक्षकों ने छात्राओं के किसी के बहकावे में आने की बात कही, वहीं छात्राओं ने स्पष्ट कहा कि वे बिना किसी दबाव के अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन तक पहुंची हैं। कलेक्टोरेट में बातचीत के बाद छात्राओं को बस से वापस हॉस्टल भेज दिया गया। कलेक्टर अजीत वसंत ने

छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बिजली व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने और मेस की साफ-सफाई तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि बिजली, शिक्षकों की कमी और मेस की साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाएगा।